हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। -वाल्तेयर

पत्रिकायन

लज्जा प्रकाश ग्रहण करने में नहीं होती, अन्धानुकरण करने में होती है। अविवेकपूर्ण ढंग से जो भी सामने पड़ गया, उसे सिर-माथे चढ़ा लेना, अन्ध-भाव से अनुकरण करना, जातिगत हीनता का परिणाम है।

हजारी प्रसाद द्विवेदी

भारत-रूस

सम्पादकीय

रूस से भारत की दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आगे बढ़ाया जाए, तो भारत को अनेक मोर्चों पर फायदा होगा।

भारत-अमरीका मैत्री के हो-हल्ले के बीच अक्सर भारत-रूस दोस्ती को भुला दिया जाता है, जबकि रूस के साथ अपनी दोस्ती को ही भारत स्वर्णिम दोस्ती कह सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह बयान स्वागतयोग्य है, 'जब भारत के संसाधन सीमित थे और उसके कुछ ही दोस्त थे, तब अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के दौरान रूस उसके साथ खड़ा था, भारत इस बात को कभी नहीं भूलेगा।' यह बात बहुत सकारात्मक और अनुकरणीय है। यह बात हम उस प्रधानमंत्री के मुंह से सुन रहे हैं, जिसे अमरीका-परस्त माना जाता है। ये वही प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अमरीका से असैन्य परमाणु करार और अमरीकी कंपनियों को भारत के रिटेल सेक्टर में उतारने के लिए अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था। दूसरी ओर, यह भी एक खुशखबरी से कम नहीं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में अगर 10 बार अमरीका गए हैं, तो 9 बार रूस गए हैं। मतलब कहीं न कहीं उन्हें भी यह अहसास है कि रूस की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सोवियत संघ के पतन की घटना व भारत द्वारा उदारीकरण को गले लगाने की घटना लगभग साथ हुई थी और उसके बाद से ही रूस-भारत दोस्ती पीछे चली गई और अमरीका-भारत की दोस्ती का ढिंढोरा पीटा जाने लगा।

निस्संदेह, भारत सरकार को रूस के साथ निकट सम्बंध रखने चाहिए और मित्रता में मजबूती का परिचय देना चाहिए। दोस्ती में हमारी दृढ़ता और ईमानदारी रूस को हमारे पक्ष में और प्रेरित करेगी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमरीका शायद भारत को उतना आगे नहीं बढ़ाएगा, जितना रूस बढ़ा सकता है। यह खुशखबरी है कि रूस जेनेवा-2 की उस वार्ता में भारत को शामिल करवाना चाहता है, जो सीरिया के मुद्दे पर होने वाली है। रूस के साथ भारत को रक्षा सहयोग का भी व्यापक विस्तार करना चाहिए। यदि हमने ऐसा किया, तो इससे चीन पर भी सकारात्मक दबाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री रूस से लौटकर अब चीन की यात्रा पर रहने वाले हैं। चीन के साथ शांतिपूर्ण सम्बंध भारत के लिए जरूरी हैं, लेकिन चीन इस बात को समझ नहीं रहा है। रूस और चीन अच्छे मित्र हैं, अतः रूस चीन को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, चीन से ईमानदार दोस्ती पाकिस्तान की भारत विरोधी कारस्तानियों पर भी अंकुश लगा सकती है। इतिहास गवाह है, रूस के साथ हमारी दोस्ती फायदेमंद रही है, इस दिशा में हमें और आगे बढ़ना चाहिए।

बात-करामात

गीतासार

खबर पढ़कर हमारी छाती फूल गई कि चीनी मूल के एक लेखक ने व्यावसायिक प्रबंधन और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता से जोड़कर गीता की प्रासंगिकता पर एक पुस्तक लिखी है। उस लेखक की तरह हमारा भी मानना है कि गीता ऐरा-गैरा ग्रंथ नहीं है। गीता ही क्यों, कोई भी महान पुस्तक आदमी को प्रबंधन ही तो सिखाती है।

पिछले दिनों एक मित्र स्वामी रामसुखदासजी की पुस्तक साधक संजीवनी हमें भेंट करके गए, बारह-तेरह सौ पृष्ठ के इस ग्रंथ को हमने जहां-तहां ही पढ़ा है। भागती-दौड़ती इस जिन्दगी में हमारे पास महाभारत, रामायण, कुरान शरीफ को बांचने का वक्त कहां है। हमने एक छोटी-सी बात पढ़ी– कर्मफल आश्रय न लेकर जो कर्म करता है, वही योगी है। अगर इस एक जुमले को आदमी जीवन में उतार ले, तो कसम से उसके सारे संताप दूर हो जाएं। पर साहब इन बातों को हम पढ़ते हैं, तो समझते नहीं। समझते हैं, तो गुणते नहीं। गुण लेते हैं तो जीवन में नहीं उतारते, क्योंकि पढ़ने, समझने और गुणने की फुरसत मिले तब न। हमें क्रिकेट के मैच, सिनेमा की चर्चा, फैशन की बहार, हीरोइन के हुस्न, नेट पर चैट से फुरसत मिले, तो कुछ पूर्वजों की कही बातों पर ध्यान दें। जहां तक प्रबंधन का प्रश्न है, तो हमारा प्रबंधन हमेशा स्त्रियों के हाथ में ही रहा है।

हमें क्रिकेट के मैच, सिनेमा की चर्चा, फैशन की बहार, नेट पर चैट से फुरसत मिले, तो पूर्वजों की बातों पर ध्यान दें।

आज भी इस देश में हमारे सरीखे करोड़ों पति हैं, जिन्हें तेल, दाल, भिंडी, बैंगन और टमाटर के बाजार भाव पता नहीं होते। प्याज के भावों की जानकारी सिर्फ इसलिए है कि टीवी समाचार वाले दिन-रात प्याज के भावों का रोना रोते रहते हैं। मानो प्याज न हुआ मोटा हीरा हो गया। वैसे अपने देश के गांवों में रहने वाले ग्रामीणजनों को जीवन प्रबंधन का शहरियों से ज्यादा ज्ञान है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने गीता को पूरा बांचा है, पर उन्होंने गीतासार दादियों और नानियों के मुंह से सुना है। पर आजकल वहां भी अराजकता हो गई है। जब से सरकारी ठेके गांव और कस्बों में खुले हैं, वहां सारा प्रबंधन अब पव्वी, अद्धी, बोतल और चटपटी नमकीन में घुस गया है। रही-सही कसर टुच्ची राजनीति ने पूरी कर दी। अब तो सिर्फ एक प्रबंधन बचा है, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, रिश्तेदारों-पड़ोसियों को नीचा दिखाओ। बेचारा चीनी लेखक। यहां आकर इस प्रबंधन पर भी उसे शोध करना चाहिए। **-राही**

महासमर (1945)

प्रच्छन्न : गोपनीय

द्रौपदी ने सोचा, 'नहीं जानता कि मेरे एक वीर पति ने अपने शस्त्र उठा लिए तो इसके बारह सहस्र योद्धा अपने प्राण बचाने के लिए दूर मरुभूमि में लोटते दिखाई देंगे।'... उसके मन में एक और विचार शृंखला समानांतर चल रही थी...

'तो वे दो अश्वारोही जो प्रातः सरिता तट पर मिले थे, इसी के सैनिक थे। वन में इन्हीं लोगों की उपस्थिति से वन्य जीव विस्थापित हुए होंगे और अपने लिए स्थान खोजने निकले होंगे। प्रातः से इस आश्रम के आसपास जो कुछ भी विचित्र घटित हो रहा था, सब इन लोगों के कारण ही था।... तो क्या ये लोग किसी पूर्व निर्धारित षड्यंत्र के अनुसार यहां वन में आकर छिप गए हैं? इन्होंने कहीं जान-बूझकर तो उसके पतियों को बहका कर दूर नहीं भेज दिया, जैसे रावण ने श्रीराम को भेज दिया था और फिर मारीच ने लक्ष्मण को भी पुकार लिया था? जाने पांडव इन लोगों की खोज में कहां भटक रहे होंगे और ये लोग यहां उनके आश्रम में आ घुसे हैं।... पर पांडव चारों दिशाओं में इन्हें खोजने निकले हैं, तो ये लोग उनकी दृष्टि से बच कैसे गए? और सहसा द्रौपदी की समझ में आ गया।... पांडवों ने काम्यकवन के इस भाग को अपना निवास बनाने के लिए इस कारण से चुना था कि इसकी पीठ पर मरुभूमि का आरंभ है। उस मार्ग से कोई यात्रा नहीं करता। पांडव उस ओर से अवश्य असावधान रहे होंगे और ये दुष्ट उसी दिशा से आकर मरुभूमि के निकट ही कहीं गोपनीय रूप से ठहर गए होंगे।

क्रमशः

नरेन्द्र कोहली

आगे बढ़ो देश गढ़ो

पोलमपोल
भायो

दोय जोड़कर दोय मैं
बता रह्या छै पांच
राजनीति मैं टिकट को
जोड़-तोड़ छै साँच

सफाई का समय › हर दल को यह ध्यान रहे कि जनता देख रही है...

दागियों के लिए बंद हों दरवाजे

- हर पार्टी चाहती है सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार
- व्यवस्था को भ्रष्ट कर देते हैं दागी प्रत्याशी
- जनता भी संकल्प ले, दागियों को करे बाहर

राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ का बड़ा कारण यह है कि राजनीतिक दलों ने चुनाव में उम्मीदवारों के चयन की कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं कर रखी, जिसमें दागियों का नेता बनने का सपना पूरा नहीं हो सके। आजादी के बाद जो लोग राजनीति में आते थे उनमें सेवा भाव रहता था, पर धीरे-धीरे सामाजिक ताने-बाने में हुए बदलाव ने राजनीति में ऐसे लोगों के लिए रास्ते खोल दिए, जो सदन की बजाय जेल के हकदार थे। चिंताजनक पहलू यह है कि हर चुनाव में राजनीतिक दलों के बड़े नेता यह कहते रहते हैं कि वे अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन जब जिताऊ उम्मीदवार का नाम आता है, तो ये दावे खोखले साबित होते नजर आते हैं।

हरीश पाराशर की रिपोर्ट...

राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी

राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर है। उनकी इस धारणा के कारण ही जनता के मन में यह बात घर कर गई है कि राजनेता और इनके दलों के कर्ता-धर्ता जो कहते हैं, उस पर तो कभी भी भरोसा करना ही नहीं चाहिए।

समय आ गया है कि राजनीतिक दल इस बारे में सोचें कि किस तरह से राजनीति का शुद्धिकरण करेंगे। यह शुद्धिकरण पार्टी के नीति-निर्धारकों के एक छोटे से कदम से भले शुरू हो, पर यह छोटा-सा कदम उठाने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। आज मतदाता की त्रासदी यह है कि उसे राजनीतिक दलों के थोपे हुए उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनना होता है। भले ही उसकी छवि कितनी भी आपराधिक रही हो। किसी को आपराधिक छवि वाला कैसे माना जाए, इसका भी स्पष्ट मापदण्ड नहीं है। राजनीतिक दलों को ही तय करना होगा कि गंभीर किस्म के अपराध में लिप्त रहे व्यक्ति को वे पार्टी से जोड़ें ही नहीं।

छंटनी करें दागदारों की

राजनीतिक दलों को टिकट वितरण की प्रक्रिया के दौरान आपराधिक छवि के लोगों को बाहर करने का काम करना होगा। टिकट के लिए आवेदन करने वाले से पहले ही इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना चाहिए कि उसके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है। साथ ही, यह भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि ऐसे किसी मामले में लिप्तता पाए जाने के साथ ही उसकी पार्टी से सदस्यता समाप्त हो जाए। एक बार राजनीतिक दल हिम्मत जुटा लें, तो कोई ताकत नहीं, जो 2013 के विधानसभा चुनावों में राजनीति की नई इबारत लिखने से रोक सके। यदि ऐसा हुआ तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इसके परिणाम साफ नजर आएंगे।

गठजोड़ है पुराना

अव्वल तो कोई राजनीतिक दल शायद ही राजस्थान समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव व अगले साल होने वाले लोकसभा के आम चुनावों में इस दावे पर खरा उतरे कि वे आपराधिक छवि वाले को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। यदि किसी ने आदर्श पेश भी कर दिया तो सवाल यह भी उठता है कि क्या चुनाव अभियान के दौरान प्रत्याशी के साथ घूमने वाले आपराधिक छवि के लोगों पर लगाम लग पाएगी? हर चुनाव में हिंसा व मारपीट की जो घटनाएं होती हैं, वे राजनेताओं के पास समाजकंटकों के जमावड़े के कारण ही होती हैं। चुनाव में राजनेता के लिए काम करेंगे, तो फिर सत्ता में आने पर नेता भी ऐसे लोगों को उपकृत तो करेंगे ही।

संगठन भी हो साफ-सुथरा

राजनीतिक दलों को जिताऊ को टिकट देने की धारणा बदलनी होगी। जिताऊ की आड़ में पार्टियां हर तरह के समझौते करती है। इसी से सारा खेल बिगड़ जाता है। लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र नजर नहीं आता है। राजनीतिक दल वास्तव में ही राजनीति में शुद्धिकरण चाहते हैं, तो उन्हें पहले एक खुफिया सैल गठित करनी होगी। यह सैल सबसे पहले संगठन में जिन लोगों को पद की जिम्मेदारी दी जा रही है, उनका पूरा रिकॉर्ड अपने स्तर पर जांचें। थानों में उसके खिलाफ कोई मामला तो नहीं है, किसी माफिया से उसके कनेक्शन तो नहीं है। बाहुबल को हथियार के रूप में इस्तेमाल तो नहीं करता। साथ ही उसकी और उसके परिवार की आय के साधन क्या है। उन आय के साधनों से अतिरिक्त यदि उसके पास धन-सम्पत्ति है, तो वह कहां से अर्जित की गई है। यदि इनकी जांच करने के बाद वह उपयुक्त पाया जाए तो ही संगठन में किसी पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसी प्रकार चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारने से पहले उसके बारे में सारा रिकॉर्ड खंगाल लेना चाहिए। खुफिया सेल को दावेदारों की सूची सौंप देनी चाहिए। यह सेल पूरी छानबीन करके ही पूरी रिपोर्ट दे।

रॉबिनहुड की छवि

कुछ राजनेता ऐसे भी हैं, जिनकी छवि साफ तौर से आपराधिक और भ्रष्ट आचरण वाली है। देश के लगभग सभी राज्यों में ऐसे सफेदपोश जरूर मिलेंगे, जो तमाम आपराधिक आचरण के बावजूद जनता की नजर में किसी मसीहा से कम नहीं हैं, लेकिन ऐसी छवि उनका बाहरी आवरण मात्र है। लोकतंत्र में ऐसे किसी आचरण को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

"सोनिया गांधी ने कई बार कहा, कांग्रेस दागियों को टिकट नहीं देगी, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के 44 सांसद दागी हैं। कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सुधार की पहल करनी चाहिए।

"भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह कई बार यह दोहरा चुके हैं, पार्टी किसी भ्रष्ट या दागी को टिकट नहीं देगी, पर लोकसभा में भाजपा के भी 44 सांसद दागी हैं और ये फिर टिकट की आस लगाए बैठे हैं।

यह भी एक अपराध

राजनीति में छवि बुरी बताने के लिए कोई आपराधिक मामला दर्ज होना ही जरूरी नहीं है। सार्वजनिक जीवन में रहने वालों पर किसी भी तरह के भ्रष्ट आचरण का आरोप सिद्ध होता है, तो उन्हें जनता का प्रतिनिधि होने का कतई हक नहीं है। रिश्वतखोरी, सरकारी धन के दुरुपयोग और चरित्रहीनता के दर्जनों प्रकरण ऐसे गाहे-बगाहे सामने आते रहते हैं जो राजनेताओं से सम्बंधित हैं। पिछले तीन दशकों की राजनीति पर नजर डालें, तो एक के बाद एक बड़े घोटालों में सीधे तौर पर नेताओं का नाम जुड़ा हुआ है। अपने फायदे के लिए धर्म-जाति के नाम पर लड़ाने में कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा करने वाले अपराधी नेताओं और उनको प्रश्रय देने वाले दलों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। यह संतोष का विषय है कि ऐसे मामलों में गत वर्षों में बड़े-बड़े राजनेताओं को जेल ही नहीं जाना पड़ा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद दिग्गजों की संसद सदस्यता भी खत्म हुई है। आपराधिक कृत्य में आर्थिक अपराध भी जुड़ा है। ऐसे लोगों को नैतिक रूप से कमजोर किए बिना राजनीति में शुचिता की कल्पना आसान नहीं है। राजनीतिक दल नहीं सुधरें, तो आखिरी हथियार मतदाता के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राइट टू रिजेक्ट का मतदान में जो प्रावधान हुआ है, उसे मतदाता के अधिकार मजबूत करने का आगाज मानना चाहिए। हालांकि इस प्रावधान मात्र से ही दागी चुनाव से बाहर नहीं हो जाएंगे। पर मतदाताओं ने चुनाव के दौरान अपराधी का चोला पहन राजनीति में घुसपैठ का प्रयास करने वालों को रोकना शुरू कर दिया, तो सभी दल उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतने लगेंगे। मतदाता भी अपने वोट की ताकत पहचानें और सिर्फ नेताओं और उनकी राजनीति को कोसना बंद करें।

बुढ़ापे के बारे में अभी से सोचे भारत

भारत में पेंशन सम्बंधी अहम विधेयक पारित हो चुका है, हालांकि इस पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण विधेयक को बनने में दस साल लग गए। अब इससे बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जिस देश में न के बराबर पेंशन सुविधा है, वहां यह कानून पेंशन विनियमन में मदद करेगा। यह हर लिहाज से शुभ समाचार है, लेकिन एक मुख्य कमी यह है कि भारत के श्रम बल का मात्र 6 प्रतिशत हिस्सा ही पेंशन संरक्षण के दायरे में आता है। बाकी 94 प्रतिशत श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। चिंता तब और बढ़ जाती है, जब हम संयुक्त राष्ट्र के इस पूर्वानुमान को देखते हैं - वर्ष 2050 तक हर पांचवा भारतीय 60 से ज्यादा उम्र का होगा। श्रम का असंगठित क्षेत्र यह सवाल पैदा करता है - हम अपनी इस बुढ़ाती आबादी के लिए क्या कर रहे हैं?

सच तो यह है कि भारत की भूसांख्यिकी का नक्शा बदल रहा है। परिवार नियोजन की कामयाबी, शिशु मृत्यु दर में कमी और चिकित्सा सुविधा में सुधार के कारण अनेक भारतीय पहले की तुलना में अधिक उम्र तक जीवित रहने लगे हैं। खास तौर पर बूढ़ी औरतों और उसमें भी विशेष रूप से विधवाओं की संख्या बढ़ी है। बुजुर्गों की जरूरतें बढ़ रही हैं, अतः जरूरी है कि हम वर्तमान पेंशन प्रणाली में यथाशीघ्र बदलाव की चर्चा करें।

विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना इसी मकसद से शुरू की गई थी कि 40 से 59 की उम्र की गरीबी रेखा के नीचे की हर महिला को हर माह 300 रुपए का अनुदान दिया जाए और इतनी ही समतुल्य राशि राज्य सरकार भी दे। लेकिन यह मदद उन विधवाओं को नहीं मिलती है, जो 40 से कम उम्र में विधवा हो जाती हैं। इसके अलावा पेंशन राशि भी अपर्याप्त है। अगर किसी विधवा का बेटा है हर साल 11,000 रुपए से ज्यादा कमाता है, तो उसे पेंशन नहीं मिलती है। यानी सरकार ने बहुत चालाकी से ऐसी लाचार विधवाओं की जिम्मेदारी उनके बच्चों पर ही डालने का रास्ता निकाल रखा है। संसद में पेंशन की जरूरतमंद विधवाओं की आयु सीमा को 18 साल करने और पेंशन राशि को बढ़ाने पर बात हो चुकी है, लेकिन ऐसा कब होगा, तय नहीं है, शायद इसके लिए अगले सुधारों का इंतजार करना पड़ेगा।

राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों की अनुसार, भारत में अकेले रहने वाले बुजुर्गों या अपने पति या पत्नी के साथ रहने वाले अकेले बुजुर्गों की संख्या मात्र एक दशक में 9 प्रतिशत से 19 प्रतिशत पर पहुंच गई है। हालांकि यह आर्थिक आजादी का भी सूचक है, लेकिन ऐसे उपेक्षितों या बुजुर्गों में बड़ी संख्या उनकी है, जो विधवा हैं या शहरी गरीब हैं। इसी वजह से इस देश को एक सशक्त पेंशन व्यवस्था की जरूरत है। इस पेंशन से परिवारों को ही मदद मिलेगी। रोजगार की मजबूरियों के कारण भी युवा अपने माता-पिता को छोड़कर दूर जा रहे हैं और हर युवा सक्षम नहीं है कि वह अपने मां-बाप या बुजुर्ग रिश्तेदार को साथ रख सके। ऐसे में, हमें जरूरतमंद बुजुर्गों की पेंशन के साथ-साथ उनकी स्वास्थ्य संरक्षण के बारे में भी सोचना होगा।

यूरोप के देश इस समय अपने बड़े-बूढ़ों की मदद के लिए भूसांख्यिकीय संकट झेल रहे हैं और इसके कारण वहां सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने पर चर्चा चल रही है और दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं और आबादी का स्थानांतरण भी हो रहा है। भारत में ऐसे नाटकीय सरकारी चिंतन की जरूरत तो एक दशक बाद ही पड़ेगी, लेकिन उम्रदराज भारत के लिए संस्थागत सुरक्षा कवच के महत्व पर अभी से विचार करना होगा और वर्तमान पेंशन प्रणालियों को लागू करने का निर्णय हमारे राष्ट्रीय एजेंडे में होना चाहिए, ताकि भविष्य में यूरोप जैसे संकट को टाला जा सके।

('कासी' के सहयोग से)

अपूर्वा जाधव
यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिलवानिया, अमरीका में शोधरत

युवा भारत को अभी से पेंशन व बुजुर्गों के सम्पूर्ण संरक्षण के बारे में सोचना होगा, ताकि यूरोप जैसी स्थिति भारत में पैदा न हो। यहां बुजुर्ग दुखी न रहें।

94
% भारतीय श्रम बल पेंशन लाभ से वंचित है।

पाठक पीठ

बेरोजगारों से छल

राजस्थान लोकसेवा आयोग से यदि सरकार भर्तियां करवाती, तो परीक्षार्थियों को एक ही फार्म भरना होता। जिला परिषद से भर्ती करवाने से हजारों ने अनेक जिलों से आवेदन किया जिसका फायदा सरकार को हुआ। लिपिक भर्ती में कोई परीक्षा नहीं हुई, जिस पर सरकार का कोई खर्च नहीं हुआ। फिर भी उसकी फीस पांच सौ रुपए रखी गई।
हेमन्त मीणा, वाया ई-मेल

किससे कहें व्यथा

चारों ओर अनाचार-भ्रष्टाचार, लूट-खसोट। प्रशासन लड़खड़ा रहा है, प्रजातंत्र भ्रष्ट हो रहा है। जन-जीवन ठगा-सा सिसक रहा है, वह व्यथा-कथा कहे भी तो किससे? राजनेता अपने स्वार्थ की पूर्ति में व्यस्त हैं। लगता है- जनभावनाओं से उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं।
डॉ. अशोक गोयल, जयपुर

अपने अमूल्य सुझावों व बेहतरीन विचारों को हमें ई-मेल करें : editor@rajasthanpatrika.com

तत्व बोध

तर्क की भाषा

एक आचार्य ने अपने शिष्य से कहा, 'जाओ, सांप की लम्बाई को नाप आओ।' शिष्य गया, एक रस्सी से उसकी लम्बाई को नाप लाया। आचार्य जो चाहते थे, वह नहीं हुआ। आचार्य ने कहा, 'जाओ, सांप के दांत गिन आओ।' शिष्य गया, उसके दांत गिनने के लिए मुंह में हाथ डाला कि सांप ने उसे काट खाया। आचार्य ने कहा, 'बस काम हो गया।' उसे कम्बल उढ़ा सुला दिया। विष की गर्मी ने उसके शरीर में से सारे कीड़ों को बाहर फेंक दिया। अधिकांश लोग जो अपने आपको कूटनीतिक मानते हैं, अहिंसा में विश्वास नहीं करते। जहां हिंसा है, बल-प्रयोग है, राजसी वृत्तियां हैं, वहां हृदय नहीं होता, छलना होती है। छलना और श्रद्धा के मार्ग दो हैं। श्रद्धा निश्छल भाव में उपजती है। जहां नेता के तर्क के प्रति अनुगामी का तर्क आता है, वहां बड़े-छोटे का भाव नहीं होता, वहां होता है- तर्क की चोट से तर्क का हनन।

आज का चतुर राजनयिक तर्क को कवच मानकर चलता है, पर यह भूल है। प्रत्यक्ष या सीधी बात के लिए तर्क आवश्यक नहीं होता। तर्क का क्षेत्र है अस्पष्टता। स्पष्टता का अर्थ है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है तर्क का अविषय। तर्क की अपेक्षा प्रेम और विश्वास अधिक सफल होते हैं। जहां तर्क होता है, वहां जाने-अनजाने दिल सन्देह से भर जाता है। अहिंसा और कोरी व्यवस्था के मार्ग दो हैं। अहिंसा के मार्ग में तर्क नहीं आता और कोरी व्यवस्था के मार्ग में प्रेम नहीं पनपता। तर्क की भाषा में दोनों को अपूर्ण कहा जा सकता है, पर प्रेम कभी अपूर्ण नहीं होता। प्रेम की अपूर्णता में ही तर्क का जन्म होता है। प्रेम की गहराई में सारे तर्क लीन हो जाते हैं।